P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-5* August- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में छात्र राजनीति ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं वर्तमान परिदृश्य

कुंवरपाल
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान

सारांश

भारत में छात्र राजनीति आजादी के पूर्व भी थी, परन्तु यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ अविच्छिन रूप से जुड़ी हुई थी युवा वर्ग ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया आजादी के बाद छात्र राजनीति की स्वतंत्र अवधारणा का विकास हुआ छात्र संगठनों ने समाज की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीति में अपराधीकरण के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट किया पर्यावरण संरक्षण एवं वर्तमान वैश्विक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी छात्रों का सकारात्मक दृष्टिकोण है। लैंगिक न्याय की स्थापना की दिशा में भी छात्र संगठन कार्यरत है।

मुख्य शब्द : छात्र राजनीति, छात्र संगठन, छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ चुनाव आचार संहिता, छात्र संघ चुनाव के उद्देश्य, लिंगदोह समिति।

प्रस्तावना

छात्र राजनीति के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, प्रथम शिक्षण संस्थानों में छात्रों की समस्याओं से अवगत होना एवं उनका युक्तियुक्त एवं तार्किक समाधान खोजना एवं द्वितीय सक्रिय राजनीति के लिए भविष्य के परिपक्व एवं श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजनेताओं का निर्माण करना, इसके अतिरिक्त छात्र संगठनों की अन्य सामाजिक मुद्दों पर जनमत की राय तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छात्र संगठन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में जानकारी एकत्रित करते हैं एवं बौद्धिक वर्ग का ध्यान उन समस्याओं की ओर लाने का प्रयास करते हैं। बौद्धिक वर्ग द्वारा निर्मित सिद्धान्तों एवं उनके विचारों पर ही राजनीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली अभिलम्बित होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

जहां तक छात्र राजनीति के उद्देश्यों की चर्चा करे तो छात्र संघों को छात्रों के हित में कार्य करना चाहिए और छात्र मूल्य आधारित छात्रनीति करें ताकि भविष्य के लिए उच्च कोटि के राजनेता बनकर समाज की सेवा कर सके, जिससे उनकी पहचान आदर्श छात्र नेता की बन सके और ऐसे नेता की पहचान समाज के स्वीकार्य नेता के रूप में हो सके।

साहित्यावलोकन

भारत में छात्र राजनीति : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं वर्तमान परिदृश्य शोध पत्र लेखन हेतु उपलब्ध साहित्य का अवलोकन किया गया है। शोध के क्षेत्र से सम्बन्धित पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का अध्ययन किया छात्र राजनीति के विषय पर विशेषज्ञों द्वारा कुछ लेख लिखे गये हैं – राजस्थान पत्रिका के संपादकीय अंक में पोफेसर के.एल.कमल का लेख "लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जगह हुडदंग हावी" आदर्श बने छात्र नेता अशोक अग्रवाल का लेख "छात्र संघ चुनाव है या आफत" लेख प्रकाशित हुए उनका साहित्य अवलोकन किया एन.सी.आर.टी. की पुस्तक के अध्याय "जन आन्दोलनों का उदय" का अध्ययन किया गया जिसम छात्रों की सक्रियता के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है। इंडियन एक्सप्रेस के दिनांक सितम्बर 7, 2006 में छपा लेख लाभदायक रहा इस शोध पत्र को लिखने हेतु जे.एम. लिंगदोह समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया गया प्रतियोगिता दर्पण के दिसम्बर 2016 के अंक में प्रकाशित आलेख "विश्वविद्यालय शिक्षा में छात्र राजनीति की प्रासंगिकता" का साहित्य अवलोकन किया गया छात्र राजनीति के ऐतिहासिक परिपक्ष्य का अध्ययन करने में "रोल ऑफ स्टूडेंट इन फ्रीडम मूवमेंट रेफरेंस टू मद्रास प्रेसीडेंसी" – कोनार्क पब्लिकेशन 1990 का अहम् योगददान रहा भारत विकासशील राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र है। यहाँ का लोकतंत्र विश्व का एक सशक्त लोकतंत्र है। लोकतंत्र में छात्र राजनीति की अनिवार्यता और अधिक गहरी हो जाती है, क्योंकि जन का, जन के

लिए, जन के द्वारा, जो शासन सुनिश्चित है उसमें जन के राजनीतिक प्रशिक्षण की महती आवश्यकता होती है। छात्र संघों को भविष्य की राजनीति की पौधशाला कहते है। छात्रों के मध्य चुनाव कराने के पीछे मूल सोच यह रहती है कि वे अपने छात्र जीवन में अपने तंत्र की खामियों, कमियों और विडम्बनाओं से उत्पन्न विचलनों को भली–भांति समझ सके, विश्वविद्यालयी जीवन में ही छात्र को जब राजनीति के पथ की व्यावहारिक कमियों एवं अच्छाइयों का ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए व्यवस्था से टकराकर उसमें सुधार लाने की क्षमता का विकास हो जाता है। छात्रों ने राजनीति के क्षितिज से उभर कर देश के विस्तृत राजनैतिक फलक पर स्वयं को स्थापित किया ह, जिसकी राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका रही है छात्र संघ के सम्बन्ध में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कहना है– छात्रसंघ का निचोड़ है कि वह छात्रों की छात्रों द्वारा तथा छात्रों के लिए गठित संगठन है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं हो। 1964 में गठित दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग के अनुसार छात्रसंघ विश्वविद्यालय के कक्षेतर जीवन में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण तरीके का प्रतीक है ढंग से संगठित छात्रसंघ स्वशासन, स्वानुशासन में सहायक है, छात्रों की ऊर्जा को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रयोग का उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान करता है। [1]

छात्र संघ और छात्र युवा आन्दोलन किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक के लिए आधार तैयार करते हैं। सरकार के जन विरोधी निर्णय एवं कार्यों के विरूद्ध आवाज उठाने का कार्य करते हैं एवं नया राजनीतिक विकल्प तैयार करने में भी मदद करते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन में छात्र युवाओं की व्यापक स्तर पर भागीदारी रही है देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ,गोरखपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय न राष्ट्रीय स्तर के नेता दिये हैं।

छात्र संघ एक सशक्त मंच है जिसके माध्यम से छात्र अपपनी सकारात्मक ऊर्जा का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। भारत का युवा वर्ग विशेषकर छात्र समुदाय भ्रष्टाचार,आतंकवाद व नक्सलवाद जैसी समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। राजनीति में अपराधीकरण एक गंभीर समस्या है जिसका शुद्धीकरण आवश्यक है। शिक्षा परिसरों में इन विषयों पर छात्र खुलकर चर्चा करते हैं। ऐसे में उचित यह होगा कि छात्रसंघों को सशक्त बनाकर छात्र राजनीति को नयी दिशा दी जाए स्वतंत्रता से पूर्व और स्वातत्रत्योत्तर भारत में जितने भी परिवर्तनकारी सामाजिक आन्दोलन हुए इनमें छात्रों की भूमिका बहुत अहम रही है।

आजादी से पहले के सभी संघर्ष अविच्छिन्न रूप से आजादी की लड़ाई से जुडे थे या कहें उन्हीं का एक लघु संस्करण थे, उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं थी, इसलिए छात्र आन्दोलन भी आजादी के प्रयासों के साथ संलग्न थे। जबकि आजादी के बाद जितने आन्दोलन हुए हैं उनके मूल में सामाजिक, राजनीतिक बदलाव की भावना निहित थी कालानुक्रम के अनुसार विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि भारतीय छात्र आन्दोलन का 150 वर्ष पुराना इतिहास है। सन् 1848 में दादा भाई नौरोजी ने 'द स्टुडेंट सांइसटिफिक एंड हिस्टोरिक सोसायटी' नामक संगठन का गठन किया। यह छात्र राजनीतिक मंच न होकर एक वाद–विवाद का मंच था। जिसका उद्देश्य शिक्षा सम्बन्धी मुद्दों पर वाद–विवाद करना था तथा सुधार की पेशकश करना था। भारत में सबसे पहली छात्र हड़ताल किंग एडवर्ड मेडिकल, लाहौर में 1913 ई. में हुई, इस हड़ताल के पीछे कारण भारतीय और यूरोपीय छात्रों के मध्य भेदभाव रहा था। हड़ताल सफल रही। कॉलेज प्रशासन ने भारतीय छात्रों की समस्याओं पर अमल किया। भारतीय छात्रों को भी वही सुविधाएँ एवं परिलाभ मिलने लगे। जो यूरोपीय छात्रों को मिलते थे। इस प्रकार जीत छात्र एकता की हुयी। [2]

1905 का स्वदेशी आन्दोलन पहला संघर्ष था जिसमें छात्रों ने बड़े पैमाने पर पहली बार भाग लिया। इस आन्दोलन का दायरा और प्रभाव काफी व्यापक था। इस आन्दोलन में युवाओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। 1907 की सूरत की फूट के उपरांत छात्रों का झुकाव कांग्रेस के गरमदल के नेताओं की ओर हो गया। छात्र बालगंगाधर तिलक के निर्देशन को स्वीकार करने लगे। तिलक की मृत्यु के बाद छात्रों को महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला। छात्रों ने 1919 के रोलेक्ट एक्ट एवं जलियावाला बाग नरसंहार का विरोध किया।

छात्रों ने पहली बार नागपुर में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया स्टुडेंट कॉफ्रेंस का अयोजन किया। इस समय छात्रों को सुभाषचन्द्र बोस एवं अन्य नेताओं का सहयोग प्राप्त था।

1920–22 के दौरान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पहले ही माह में लगभग 90,000 छात्रों ने विद्यालय एवं महाविद्यालयों को छोड़ दिया और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लिया। इस समय देश में लगभग 800 विद्यालय एवं महाविद्यालय थे।

सम्पूर्ण देश में शिक्षा का सामूहिक बहिष्कार हुआ, परन्तु आन्दोलन का व्यापक असर बंगाल में देखा गया। उसी समय इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में कई नये विश्वविद्यालयों की भी नींव रखी गयी जिनमें काशी हिन्दू महाविद्यालय और काशी विद्यापीठ प्रमुख है।। इन विश्वविद्यालयों ने कालान्तर में नए क्रांतिकारियों को पैदा किया और आजादो के बाद भी छात्र आन्दोलन के लिए प्रेरणा स्रोत होते रहे हैं।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन में विदेशी कपड़ों और मदिरा के बहिष्कार में छात्रों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। असम में 'कनिघम सर्कुलर', के विरोध में छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आन्दोलन चलाया गया जिसमें छात्रों एवं उनके अभिभावकों से सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

1938 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का विभाजन दो भागों, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के रूप में हुआ।

भारत छोड़ो आन्दोलन में हालांकि समाज के सभी वर्गों की सहकारिता रही, लेकिन आन्दोलन की

खबरों को गाँव–गाँव तक पहुँचाने में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

1950 के बाद छात्र राजनीति

आजादी के बाद भी छात्रो ने सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान के प्रयास की दिशा में आन्दोलन किया। 1950 के दशक में असमिया छात्रों के नेतृत्व में एक आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिसमें राज्य सरकार की नौकरियों में असमी भाषी लोगों को प्राथमिकता देना, असमिया को राज्य की एकमात्र सरकारी भाषा एवं स्कूल तथा कालेज में पढ़ाई का माध्यम बनाने का मुद्दा प्रमुख था।

असम में गैर कानूनी आमजन की समस्या का मुद्दा 1950 से ही उठता रहा है। असम की मतदाता सूची से इनके नाम को हटाने के लिये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (ए.ए.एस.यू.) ने असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर गैर कानूनी प्रवासियों के विरूद्ध आन्दोलन प्रारंभ कर दिया। [3]

आजादी के बाद छात्रों की चिपको आन्दोलन में,एंटी इमरजसी मूवमेंट, मंडल आन्दोलन आदि में सक्रिय रूप से भागीदारी रही है।।

आजादी के बाद छात्रों का सबसे बड़ा आन्दोलन बिहार आन्दोलन था। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों से सम्पूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए एक वर्ष तक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद रखने का आहवान किया। छात्रों की मांगे थी कि भ्रष्टाचार का अंत हो, बेरोजगारी का निराकरण हो तथा शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। पांच जून 1974 को पटना के गांधी मदान में जे.पी. ने कहा 'यह क्रांति है मित्रों और सम्पूर्ण क्रांति है, विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है। यह तो महज मील का पत्थर है, हमारी मंजिल तो बहुत दूर है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है।'[4]

छात्रों ने छात्र संघर्ष समिति का गठन किया, जिसका गठन पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया गया। जिसके अध्यक्ष लालू प्रसाद बनाये गये एवं सुशील कुमार मोदी महासचिव चुने गये, रामविलास पासवान भी इस आन्दोलन की उपज थे। इस आन्दोलन में छात्रों ने अपने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस आन्दोलन में छात्र नेता विद्यानंद तिवारी सम्मिलित थे। जे. पी. के आहवान पर छात्रों ने बिहार विधानसभा के सामने धरना दिया तथा विधायकों से त्यागपत्र की मांग की, जिलाधीश कार्यालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन किये।

नव–निर्माण आन्दोलन

पाकिस्तान युद्ध की सफलता एवं 'गरीबी हटाओं' के नारे से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता शिखर पर पहुँच गयी थी कि तत्कालीन समय में "भारत इंदिरा है, इंदिरा भारत है" (India is Indira, Indira is India) कहावत प्रचलित थी। उसी समय इंदिरा गांधी ने गुजरात में पटेल को कुर्सी पर बैठाया। जनता मँहगाई व भ्रष्टाचार से परेशान थी। छात्रों ने इसके विरूद्ध मोर्चा खोल दिया जिन्हे आर.एस.एस. एवं ए.बी.वी.पी. का समर्थन प्राप्त था। इस आन्दोलन का प्रभाव था कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। [5]

1974 में उत्तरांचल के चिमोली जिले में चिपको आन्दोलन चलाया गया। [6]

गाँव की महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर 'वृक्ष बचाओ' अभियान चलाया। इसकी सहायता से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र–छात्राएं आगे आये। पर्यावरण संरक्षण में इस अभियान का विशेष स्थान है, जिसने भारत के जनमानस का ध्यान अपनी और आकृष्ट किया। इसके उपरान्त पर्यावरण संरक्षण के अन्य कार्यक्रम देशभर में चलाए गये।

छात्र सक्रियता दलित उत्थान के क्षत्र में भी रही। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के निर्देशन में दलित समाज के छात्र संगठिन होना आरंभ हुए इन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित छात्र संघ नामक संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य संगठन का विस्तारित एवं सुदृढ़ के साथ–साथ निम्न वर्ग को अपने अधिकार के बारे में जागृत करना था। 1961 में रिपब्लिक युवक संगठन बना यह पहला दलित छात्र आन्दोलनकारी संगठन था जिसके नीचे दलित छात्रों ने आन्दोलन करना आरंभ किया।

1967 में विदर्भ रिपब्लिक छात्र संघ (VRSF) नामक संगठन निर्मित हुआ। इसकी तीन कान्फ्रेंस हुई। इन सभी सम्मेलनों में महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर एवं अम्बेडकर जी के विचारों एवं कार्यों की सराहना की गयी। महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं ने मिलकर 'दलित पेन्थर्स' नामक संगठन बनाया। [7]

इसका उद्देश्य दलितों के हितों की दावेदारी प्रस्तुत करना था। 1990 में वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। दिल्ली के सेन्ट स्टीफन कॉलेज एवं दिल्ली स्कूल ऑफ इकानामिक्स के छात्र एकत्रित हुए एवं इस आरक्षण के विरोध में नारे लगाकर विरोध प्रदर्शित किया।

निर्भया कांड

छात्रों एवं छात्र संगठनों ने समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता प्रकट की है। निर्भया कांड निर्भया कांड के दौरान छात्र–छात्राओं ने देश के सभी भागों में प्रदर्शन किया। इस घटना के विरोध में देश के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालया में शोक सभा हुई, मोमबत्तियाँ जलाकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो इसके लिए सरकार और राष्ट्र की जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अनेक प्रयास किये गये, शांति मार्च निकाले गये, पोस्टर और बैनरों द्वारा विरोध दर्शाया गया।

अन्ना आन्दोलन में छात्रों की सक्रियता

भ्रष्टाचार के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में 25 जून 2011 को आन्दोलन प्रारंभ किया गया जिसमें 15–35 आयु के हजारों युवाओं ने भाग लिया। इस आन्दोलन में विशेष रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं एस.एफ.आई. छात्र संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 'यूथ अगेंस्ट करप्शन' नामक संस्था का सृजन किया। इस संस्था के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी जनजागृति फैलाने का कार्य किया गया।

जे.पी. के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन में छात्रों की सक्रियता निर्णायक रही, परन्तु उनके बाद धीरे–धीरे

छात्र संघ अपने मूल उद्देश्य से भटकते हुए प्रतीत हुए। छात्र गुटों के मध्य हिंसक घटनाएँ भी देखी गयी। राजस्थान के सांगरिया कस्बे में छात्र गुटों के बीच झगड़ा इतना बढ गया कि गोलीबारी की घटना तक हो गयी, जिसमें दो छात्रों की मौत हो गयी। छात्र संघ चुनावों में चुनाव प्रचार में खर्च सीमा का उल्लंघन होता देखा गया है। चुनाव में छात्र मंहगी आरामदायक गाडियों का प्रयोग लेते हैं, चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है। पोस्टर्स, बैनर एवं प्लेक्स का अत्यधिक प्रयोग हुआ है जिससे शहर की सड़के एवं दीवारें बदरंग दिखाई पडती है। छात्र राजनीति में टिकट वितरण एवं उसके बाद मतदान के समय जातिगत समीकरणों का खेल भी देखा गया है। वर्तमान म छात्र राजनीति मुख्यधारा की राजनीति में घुसने का माध्यम यानि 'लांचिगपैड़' है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के शिशु लोकतंत्र में लोकतंत्र की वर्णमाला के सिखाने, युवा छात्र शक्ति को एकजुट बनाकर सही दिशा में ले जाने का उद्देश्य गत वर्षों में धूमिल हो गया है। जे.पो.आन्दोलन के छात्र नेताओं की टिकट पक्की क्या हुई छात्र राजनीति के हरे भरे वृक्ष में भी अनेक दुर्गुणों का समावेश होने लगा है।[8]

सुप्रीम कोट छात्रसंघ चुनावों के दौरान हुडदग रोकने के लिये सख्त नियम बना चुका है परन्तु प्रशासन आज तक इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कर सका है। छात्रसंघ चुनाव आते ही शहरों में छात्रों के काफिले जनजीवन को अस्त–व्यस्त करते दिखाई देते हैं। प्रतिबंध के बावजूद दीवारें पोस्टरों से बदरंग हो जाती है। पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। माहौल हिंसक हो जाता है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के आस–पास तो हुडदंगी छात्रों का ही राज हो जाता है। महिलाएँ असुरक्षित महसूस करने लगती है और लोग आने जाने के लिए दूसरे महफूज रास्ते ढूंढने लगते हैं।[9]

छात्र राजनीति में धन, बल और बाहुबल का खेल खुल्लेआम देखा जा सकता है। सत्य यह है कि लम्पट अपराधी ओर अराजक छात्र मौजूदा शैक्षिणक अराजकता का ही परिणाम है इस शैक्षिक अराजकता के लिए केन्द्र और प्रदेश की सरकारों के साथ–साथ विश्वविद्यालय प्रशासन मुख्यरूप से जिम्मेदार है। सरस्वती के आंगन में इस प्रकार की घटनाओं का होना बहुत ही अशोभनिय बात है।

इसलिये कइ राज्यों में विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव या तो अनियमित रूप से होते हैं या उन्हें अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में सन् 2008 से 2011 तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। राजस्थान में प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में माननीय उच्च न्यायालय ने 2005 से छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया जो सत्र 2010–11 से पुनः प्रारंभ हुआ। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 1997 के बाद कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है।[10]

छात्र संघ चुनावों में उत्पन्न दोषों के निवारण हेत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त जे.एम. लिंगदोह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जिसने 2006 में छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की।[11]

1. उम्मीदवार सिर्फ 5000 रूपये तक ही खर्च कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव के बाद दो सप्ताह की अवधि में चुनाव अधिकारी को खर्च के अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे।
2. अधिक धन राशि खर्च करने की स्थिति में उम्मीदवार का चुनाव रद्द किये जाने का प्रावधान।
3. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके संगठन, राजनीतिक दलों से चन्दा नहीं ले सकते।
4. चुनावों में प्रचार के लिए हाथ से बनाए गए पोस्टर ही काम में लिए जा सकते हैं, छपे हुए नहीं। इसका उपयोग भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही उपयोग हो सकेगा।
5. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के बाहर कोई भी उम्मीदवार रैलियां या सभा नहीं कर सकता। शिक्षण संस्थान के बाहर प्रचार सामग्री भी वितरित नहीं की जा सकती विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में रैली या सभा के लिए भी सम्बन्धित संस्था प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
6. छात्र संघ चुनावों का कोई भी उम्मीदवार ऐसी क्रिया–प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त न हो जिससे जाति, धर्म, सम्प्रदायों के बीच आपसी वैमनस्य उत्पन्न हो, दूसरे उम्मीदवारों की सिर्फ आलोचना की जा सकती है। निजी जीवन सम्बन्धी आलोचना नहीं की जा सकती।
7. छात्र संघ चुनावों के प्रचार में लाउडस्पीकर या वाहनों का उपयोग नहीं हो सकता।[12]

गत दो–तीन वर्ष से छात्रों एवं गतिविधियों में परिवर्तन देखा गया है। छात्र संगठन, छात्र राजनीति की मर्यादाओं में रहकर कार्य कर रहे हैं। छात्रसंघ चुनावों के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों की तरह चुनाव आचार संहिताओं का उल्लंघन करते कम ही नजर आये हैं।

हस्तलिखित पोस्टर्स के माध्यम से चुनाव प्रचार करते हैं। महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय परिसर में ही प्रचार की गतिविधियां देखी जाती है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों को उदाहरण के रूप में लिया जाये तो ज्ञात होता है कि हिंसक घटनाओं में कमी आयी है। इसे विद्यार्थियों की सोच में बदलाव भी माना जा सकता है और लिगदोह समिति की सिफारिशों का प्रभाव। परन्तु परिणाम सकारात्मक अवश्य देखे गये हैं। प्रशासन का नजरिया भी पहले की तुलना में अधिक सख्त रहा है। अनुशासन स्थापित करने के लिए नियमों का कठोरतापूर्वक पालन किया गया है। चुनावी खर्च की सीमा अभी भी एक विचारणीय बिन्दु है। छात्र राजनीति में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। छात्र राजनीति अपने मूल उद्देश्य के इर्द–गिर्द अपने आपको सीमित रखती है तो यह छात्र राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चुनाव आयोग जैसा निकाय विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो केवल नियमों के दायरे में चुनाव निपटाने, शिकायतों पर कार्यवाही करने का कार्य करे।[13]

निष्कर्ष

वर्तमान समय में छात्र राजनीति में कुछ दुर्गुणों का समावेश हो गया है इस कारण कुछ विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया है। छात्र संघ की राजनीति को गुण्डों और अपराधियों से मुक्त कराने के नाम पर विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंटना उचित नहीं है, परन्तु वर्तमान में अधिकांश छात्रसंघों को देखते हुए कुछ सुधार की गुंजाइश अवश्य बनती है। छात्र नेताओं का यह दायित्व बनता है कि वे दलगत राजनोति या गुटबंदी से ऊपर उठकर गुटनिरपेक्ष छात्र राजनीति पर चिंतन–मनन करे तथा युवाओं में इसके प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *विश्वविद्यालय शिक्षा में छात्र संघ की प्रासंगिकता, प्रतियोगिता पर्दण (मासिक), साहित्य भवन प्रकाशन, दिसम्बर, 2016, 1888*
2. *Role of student in freedom movement reference to Madras presidency – V. Sankaran Nair कोनार्क पब्लिकेशन, 1990*
3. *भारतीय राज व्यवस्था बी.एल. कडिया, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा, पृष्ठ 48*
4. *स्वतंत्र भारत में राजनीति, एन.सी.ई.आर.टी. कक्षा 12, पृष्ठ 62*
5. *स्वतंत्र भारत में राजनीति, एन.सी.ई.आर.टी., कक्षा 12, पृष्ठ 52*
6. *स्वतंत्र भारत में राजनीति, एन.सी.ई.आर.टी., कक्षा 12, पृष्ठ 72*
7. *स्वतंत्र भारत में राजनीति, एन.सी.ई.आर.टी., कक्षा 12, पृष्ठ 60*
8. *विश्वविद्यालय शिक्षा में छात्रसंघ की प्रासंगिकता प्रतियोगिता दर्पण (मासिक), साहित्य नवम प्रकाशन, आगरा, दिसम्बर 2016, पृष्ठ 1888*
9. *के.एल. कमल पूर्व कुलपति राजस्थान यूनिवर्सीटी लेख छात्रसंघ : लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जगह हुडदंग हावी। राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 21,8,2014*
10. *इण्डियन एक्सप्रेस, सितम्बर 7, 2016*
11. *लेख आदर्श बने छात्र नेता, राजस्थान पत्रिका, 1.12. 2014*
12. *लिंगदोह समिति रिपोर्ट*
13. *अशोक अग्रवाल, ज्युरिस्ट लेख – छात्र संघ चुनाव है या आफत, राजस्थान पत्रिका, 2010,19*